हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 161 लखनऊ, बुधवार 04 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से मेक इन इंडिया प्रयासों को मिलेगी मजबूती

विकास को मिलेगी गति : जयशंकर

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए मंगलवार को कहा कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास को गति मिलेगी और देश के मेक इन इंडिया प्रयासों को मजबूती मिलेगी। जयशंकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर अमेरिका के नेतृत्व में हो रही मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि वह श्द्विपक्षीय व्यापार पर की गई घोषणाओं का स्वागत करते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला जवाबी शुल्क मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, इससे अधिक नौकरियां पैदा होंगी, विकास को बढ़ावा मिलेगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में नवोन्मेष को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मेक इन इंडिया के प्रयास मजबूत होंगे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वसनीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, हमारे आर्थिक सहयोग में अपार संभावनाएं हैं और हमें विश्वास है कि हम उन्हें साकार कर लेंगे। एक मजबूत आर्थिक संबंध हमारी रणनीतिक साझेदारी की सबसे मजबूत नींव है। व्यापार समझौते की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। इस बात की खुशी है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क घटकर 18 फीसदी रह जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, 8 से 10 जून तक होगी लिखित परीक्षा

प्रदेश में कुल 32,679 पदों के लिए तीन दिन होगी लिखित परीक्षा, दो पालियों में होगा आयोजन

लखनऊ ब्यूरो

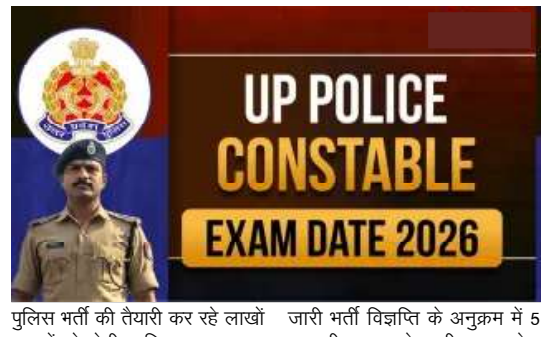

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के तहत होने वाली लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (न्च्च्ठच्ठ) की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार सिपाही भर्ती–2025 की लिखित परीक्षा 8 जून (सोमवार), 9 जून (मंगलवार) और 10 जून (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा तीनों दिनों में दो–दो पालियों में कराई जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 32,679 पदों को भरा जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी, परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड एवं दिशा–निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत बना योगी सरकार का फैसला

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में

पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्तमान सिपाही भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती–2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली–1992 के नियम–3 के आलोक में लिया गया। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में प्रदेश में कांस्टेबल के कुल 60,244 पदों पर भर्तियां की गई थीं। यह प्रदेश सरकार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी पदों में से 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हुए उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है।

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी की नसीहत–एनडीए नेताओं को अनेक चुनावों में जीत पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं से मंगलवार को कहा कि गठबंधन अपनी जन–केंद्रित नीतियों एवं कड़ी मेहनत की वजह से विभिन्न चुनाव जीत रहा है और उसके नेताओं को चुनावी विजय को लेकर आत्मसंतुष्टि की भावना से बचना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजग संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजग के घटक दलों के सांसदों से कहा कि उन्हें स्थानीय निकाय समेत विभिन्न चुनावों में अपनी जीत से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि अच्छा काम करते रहना चाहिए।

अमेरिकी ट्रेड डील पर राहुल बोले- मोदी ने देश बेचा, अडाणी पर केस और एपस्टीन फाइल्स से पीएम डरे हुए

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में देश बेच दिया है। आपकी मेहनत को खून–पसीने को बेच दिया है, क्योंकि वे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब यह इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, यह असल में मोदी पर केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। उसकी वजह से भी पीएम पर प्रेशर है। ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। देश को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल ने कहा कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है। जनता को इस बारे में सोचने की जरूरत है। दरअसल, ट्रम्प ने सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान किया।

इतिहास में पहली बार, 12 महीने में 5 Trade Deals, क्यों हिंदुस्तान संग बिजनेस करने को आतुर है दुनिया

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत के आर्थिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ ही दिनों में देश ने दो बड़े–बड़े व्यापारिक समझौते कर लिए हैं। पूरे साल की बात करें तो भारत ने कुल पांच प्रमुख ट्रेड डील साइन की हैं, और इन समझौतों वाले देशों की मिली–जुली जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 50% से भी ज्यादा है। सबसे नई और ताजा डील अमेरिका के साथ हुई है, जो पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव और टैरिफ की वजह से चर्चा में बनी हुई थी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, जहां पिछले वित्त वर्ष (2025) में भारत के कुल निर्यात का करीब 20% माल गया और हमारे आयात में उनकी हिस्सेदारी 6.3% रही। वर्ष 2014 से अब तक भारत ने आठ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया है। भारत ने पिछले कुछ वर्ष में 37 विकसित देशों के साथ आठ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया है। दूसरी तरफ भारत चिली, पेरू और कनाडा सहित कई देशों के साथ इसी तरह के समझौतों के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। चिली के साथ व्यापार वार्ता लगभग अंतिम चरण में है जहां भारत के महत्वपूर्ण खनिजों में हित हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र के छह देशों के समूह जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषदने) भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है।

हर कोई भारत के साथ बिजनेस क्यों करना चाहता है?

दुनिया में कई बड़े देश आजकल मंदी या परेशानी में हैं, लेकिन भारत लगातार 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ सब कुछ काफी स्थिर और भरोसेमंद है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं और इनमें से बहुत सारे लोग अब मध्यम वर्ग के हैं – यानी उनके पास पैसे हैं, वे सामान खरीदते हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी के लिए यह सबसे अच्छा ग्राहक आधार है। कई कंपनियां अब चीन में फैक्ट्री चलाने की जगह दूसरा देश ढूंढ रही हैं। भारत अपनी PLI स्कीम (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) के जरिए उन्हें अच्छी सुविधाएं और मदद दे रहा है। भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है। साथ ही डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आजकल लगभग हर देश और हर बड़ी कंपनी भारत से जुड़ना चाहती है।

और भी गुड न्यूज आ सकती है

आने वाले वर्ष में भारत के लिए निश्चित रूप से और भी कई अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। भारत एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनेगा। व्यापार समझौतों के तहत, दो या दो से अधिक राष्ट्र अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर आयात शुल्क या तो समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं। वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील भी देते हैं।

बाराबंकी में एनआईए, एटीएस व एसटीएफ की संयुक्त दबिश, हिरासत में युवक, इलाके में हड़कंप

संवाददाता/बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मंगलवार सुबह करीब आठ बजे एनआईए, एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियों की अचानक दबिश से इलाके में हड़कंप मच गया और तरह–तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि कार्रवाई के कारणों का आधिकारिक खुलासा अब तक नहीं किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार संयुक्त टीमें शहर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल पहुंचीं, जहां से रामलखन नामक युवक को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि वह अस्पताल में भर्ती अपनी मां की देखभाल के लिए मौजूद था। इसके बाद टीमें बदोसराय थाना क्षेत्र के खोर एत्महादपुर गांव स्थित उसके घर पहुंचीं और कई घंटों तक गहन तलाशी ली। स्थानीय पुलिस बल भी कार्रवाई के दौरान तैनात रहा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तलाशी में कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। कार्रवाई के बाद युवक के कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन एजेंसियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने पुष्टि की कि केंद्रीय एजेंसियों ने दबिश दी है, मगर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। स्थानीय स्तर पर भी जांच जारी है।

हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, आसन की ओर कागज उछालने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्ष के आठ सदस्य निलंबित

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को आसन के समीप कागज उछालकर सदन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के सात सदस्यों

और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक सांसद को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आठों सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374 (2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछालकर फेंके थे। राहुल गांधी ने मंगलवार को सदन में नरवणे की पुस्तक पर आधारित लेख को सत्यापित करते हुए सदन के पटल पर रखा। उन्होंने फिर से नरवणे के संस्मरण और चीन के साथ टकराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबंध है और यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रमुख हिस्सा है। आसन से उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

व्हाट्सऐप-मेटा की डेटा शेयरिंग नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त आपत्ति, कहा, निजता के अधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता नीति को लेकर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सऐप को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां श्डेटा साझा करने के नाम पर नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वह नौ फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को याचिकाओं में पक्षकार बनाया जाए। पीठ मेटा और व्हाट्सऐप की उन अपीलों पर

सुनवाई कर रही थी, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसने विज्ञापन से जुड़े डेटा साझा करने के मामले में सीमित राहत देते हुए प्रभुत्व के दुरुपयोग संबंधी सीसीआई के निष्कर्षों को बरकरार रखा था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, आप डेटा साझा करने के नाम पर इस देश के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम आपको डेटा का एक शब्द भी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे, या तो आप लिखित वचन (अंडरटेकिंग) दें... आप नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि इस देश में निजता के अधिकार की सख्ती से रक्षा की जाती है। उसने कहा कि गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि आम व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं सकता। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह निजी जानकारी की चोरी करने का एक सभ्य तरीका है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे... आपको लिखित वचन देना होगा, अन्यथा हमें आदेश पारित करना होगा।

हरदोई, लखनऊ राजमार्ग पर कंटेनर से भिड़ी बस, चालक की मौत, नौ यात्री घायल

एजेंसी

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हरदोईदृलखनऊ राजमार्ग पर कटिया मऊ गांव के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार निजी बस ने एक कंटेनर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बस चालक की मौत हो गयी जबकि नौ यात्री घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर राजमार्ग किनारे खाई में जा गिरी, जिससे घटनास्थल पर अफरा–तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को जिले के कोतवाली कछौना क्षेत्र के अंतर्गत हरदोईदृलखनऊ राजमार्ग के पास हरदोई से लखनऊ जा रही बस तेज गति में थी। इसी दौरान मल्हपुर रेलवे क्रॉसिंग की ओर से आ रहा एक कंटेनर जैसे ही लखनऊ की दिशा में मुड़ा, बस चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और यह दुर्घटना हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) सुबोध गौतम ने बताया कि हादसे के वक्त बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। यात्रियों की चीख–पुकार सुनकर दुर्घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस की मदद से तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना

पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद बस चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया।पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस की बॉडी काटकर चालक को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने बस चालक राजू उर्फ गोपाल (45) को मृत घोषित कर दिया।

शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस सांसद के बीच सुलझा विवाद, मानहानि केस में हुआ समझौता

एजेंसी

भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के बीच मानहानि का विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में रिकॉर्ड दर्ज किया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन.के. सिंह की बेंच पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तन्खा की शिकायत पर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्टियों ने संसद में मुलाकात के बाद अपने मतभेद सुलझा लिए हैं। जेठमलानी ने कहा, हमें अदालत को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे मुवक्किल और तन्खा संसद में मिले और मामला सुलझा लिया। तन्खा मानहानि का अपना सिविल मुकदमा और आपराधिक शिकायत दोनों वापस ले लेंगे। इस बात पर ध्यान देते हुए, जस्टिस सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि राजनेताओं से उच्च स्तर की सहनशीलता की उम्मीद की जाती है। देखिए, वे सांसद हैं, वे ज़्यादा मोटी चमड़ी वाले होते हैं! राजनेताओं की भाषा अलग होती है, और ज़्यादा संवेदनशील होने से बचना चाहिए क्योंकि यह उनके काम का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। एसएलपी का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहारू ष्हमें सूचित किया गया है कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। हम अपनी सराहना व्यक्त कर रहे हैं। पार्टियों के बीच सभी लंबित विवाद समाप्त हो गए हैं, जिसमें आपराधिक शिकायत और मानहानि का मामला दोनों शामिल हैं। 11 नवंबर, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की तिकड़ी को अंतरिम राहत दी, और निर्देश दिया कि उन्हें जमानत योग्य वारंट के अधीन नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रभावी रूप से भाग लें। याचिकाकर्ताओं

ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया था जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तन्खा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

संपादकीय

अमरीका में भारतीयों के बुरे दिन

2023 में अमरीका के कोलेरेडो विश्वविद्यालय में एक दम्पति, आदित्य प्रकाश और उर्मि भट्टाचार्य पीएच.डी. कर रहे थे। वे वहां अपना लंच ओवन में गर्म कर रहे थे। खाने में पालक–पनीर था। लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें खाना गर्म करने से रोक दिया। उनका कहना था कि इसमें से बदबू आ रही है, इसलिए इसे यहां गर्म नहीं किया जा सकता। यह भी कि हम तो यहां ब्रोकली भी गर्म नहीं करने देते। इस बात की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की गई। उर्मि वहां शिक्षिका भी थीं। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। दोनों को पीएच.डी. की डिग्री भी नहीं दी गई। तब इन दोनों ने न्यायालय में शिकायत की कि मामूली–सी बात को इतना बड़ा बना दिया गया। उन्हें तरह–तरह से तंग किया गया और डिग्री भी नहीं मिली। अदालत ने प्रशासन को आदेश दिया कि इस दम्पति को दो लाख डालर मुआवजे के रूप में दे। उनकी पीएच.डी. की डिग्री भी दी गई। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमेशा के लिए अपने यहां उन्हें बैन कर दिया। जिस मामले में इन दोनों का कोई दोष नहीं था, उसके लिए इन्हें इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। याद रहे कि यह ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने से पहले की बात है। इन दिनों वहां प्रशासन लगातार भारतीयों पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि नौकरियां सिर्फ अमरीकी लोगों को ही दी जाएं। इनमें भी बिना कहे गोरों को प्राथमिकता दी जाए। पिछले दिनों टैक्सास विश्वविद्यालय में भी ऐसी ही गाइडलाइंस भेजी गईं। अब तक लोग समझ रहे थे कि एच1 बी वीजा के शिकार सिर्फ आई.टी. सैक्टर के लोग ही बनेंगे, मगर अब यूनिर्वसिटीज भी इससे नहीं बच रहीं। जिस अमरीका ने पूरी दुनिया को अस्मिता मूलक विमर्श के चश्मे से देखने की आदत डाल दी, अब वही इससे पांव खींच रहा है। वे इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि यदि अमरीका में लोग इतने ही मेहनती होते, तो बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। कुछ समय पहले बिल गेट्स ने कहा था कि अगर हम भारतीयों को रोकेंगे, तो वे अपना गूगल खुद बना लेंगे। लेकिन नफरती नेताओं को यह बात भला क्यों समझ में आने लगी। प्रशासन की शह पाकर इन दिनों अमरीका में भारतीयों के खिलाफ लगातार घृणा फैलाई जा रही है। उन पर हमले बोले जा रहे हैं। पीछा किया जा रहा है। बच्चों को स्कूलों में परेशान किया जा रहा है। लोग दीवाली मनाने की शिकायत कर रहे हैं। भारतीयों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं कि अपने देश वापस जाओ। उनके बारे में तरह–तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि वे गोबर खाते हैं। गौ मूत्र पीते हैं। वे अमरीका को बर्बाद करने के लिए आए हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कई साल पहले पोलैंड में घूमते एक भारतीय को एक अमरीकी ने रोककर कहा था कि तुम यहां भी आ पहुंचे। अपने देश वापस जाओ। दरअसल जब सरकारों के पास अपने वोटरों को देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वे वैमनस्य के विचारों और नारों को हवा देती हैं। लोगों को एक–दूसरे से लड़वाकर नेता चांदी काटते हैं। जोहरान ममदानी जब न्यूयार्क के मेयर का चुनाव जीते, उस समय यह लेखिका न्यूयार्क में ही थी। जिस वर्ल्ड ट्रेड सैंटर को 9/11 को तोड़ा गया था, वह अब दोबारा बन गया है। उसके नीचे खड़ी यही सोच रही थी कि इसे तोडने में आप्रवासियों का ही हाथ बताया गया था लेकिन अब क्या हुआ कि ममदानी के खिलाफ लगातार दिए बयानों के बावजूद, वह जीत गए। ध्यान से देखें, तो न्यूयार्क में बाहर से आए लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से आप्रवासियों को निशाना बनाया गया, इससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ी। उन्हें लगा कि ममदानी उनके पक्ष में लगातार बोलते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, इसलिए उन्हें जिता दिया। अमरीका, अमरीकी लोगों के लिए ही है, यह बात तो ठीक है, लेकिन खुद अमरीका के गोरे वहां के मूल निवासी नहीं हैं। वे भी बाहर से आए और उन्होंने वहां के मूल निवासियों को तहस–नहस कर दिया। 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का जो नारा दिया गया है, अर्से से भारतीय उसी में योगदान दे रहे हैं। सिलिकॉन वैली को सफल बनाने में भारतीयों का ही बड़ा हाथ है। भारतीय डाक्टरों को अमरीका में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि वे मरीजों की बात सुनते हैं, उन्हें ढांढस भी बंधाते हैं। जबकि अमरीका में आम डाक्टर का 3 महीने से पहले टाइम भी मिलना मुश्किल होता है। अस्पताल में जाना पड़े, तो बहुत देर बाद ही चिकित्सकीय सहायता मिल पाती है। इन सब बातों को देखकर सत्तर के दशक की याद आती है। जब युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन ने पीढियों से रह रहे भारतीयों को वहां से खदेड़ा था। उनके बैंक अकाऊंट भी फ्रीज कर दिए गए थे। उस समय ईदी अमीन के अत्याचार बहुत सुर्खियां भी बने थे। अमरीका एक उदार देश रहा है। उसकी यही छवि उसे महान भी बनाती है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पूरे विश्व में अब उदारता के दिन लद गए हैं।

नर्सरी से कॉलेज तक, एडमिशन की युद्धभूमि

दाखिले की दौड़ में बच्चों पर बढ़ता दबाव और प्रतिस्पर्धा

—डॉ० सत्यवान सौरभ

आज शिक्षा का अर्थ सीखना नहीं, बल्कि साबित करना हो गया है। साबित करना कि बच्चा बेहतर है, तेज़ है, दूसरों से आगे है। और यह साबित करने की ज़िम्मेदारी बच्चे से ज़्यादा उसके माता–पिता के कंधों पर डाल दी गई है। नतीजा यह है कि नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, 'दाख़िला' अब एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव का कारण बन चुका है। दाख़िले की इस दौड़ में सबसे पहले निशाने पर आता है मासूम बच्चा। वह उम्र, जब खेलना, कल्पना करना और सवाल पूछना चाहिए, उसी उम्र में उसे फ़ॉर्म, इंटरव्यू, टेस्ट और रैंक के बोझ तले दबा दिया जाता है। नर्सरी एडमिशन के नाम पर माता–पिता छुट्टियाँ लेते हैं, स्कूल–दर–स्कूल भटकते हैं, सिफ़ारिशें ढूँढते हैं और कई बार आत्मसम्मान तक गिरवी रख देते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि बच्चा सीख सके, बल्कि इसलिए कि वह 'अच्छे स्कूल' का टैग हासिल कर सके। आज शिक्षा संस्थान ज्ञान के मंदिर कम और प्रतिस्पर्धी बाज़ार ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अख़बारों में 'मिशन एडमिशन' जैसे शब्द आम हो चुके हैं। टीवी चौनलों पर दाख़िले को लेकर बहसें होती हैं, कोचिंग संस्थान भविष्य की गारंटी बेचते हैं और स्कूल–कॉलेज अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाने में लगे रहते हैं। इस पूरे तंत्र में बच्चा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन जाता हैकृजिसे हर हाल में सफल दिखाना ज़रूरी है। कभी 60–65 प्रतिशत अंक लाना सम्मान की बात हुआ करती थी। सेकंड डिविज़न जीवन की हार नहीं मानी जाती थी। आज हालात यह हैं कि 90 प्रतिशत से नीचे अंक लाने वाला बच्चा और उसके माता–पिता अपराधबोध में जीते हैं। 95–96 प्रतिशत अंक लाने वालों को भी चौन नहीं है, क्योंकि कट–ऑफ़ हर साल नई ऊँचाई छू रहा है। ऐसा लगता है मानो अंकों की इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब ज़्यादातर बच्चे 90 प्रतिशत से ऊपर अंक ला रहे हैं, तो क्या वास्तव में सब असाधारण प्रतिभाशाली हैं? या फिर मूल्यांकन प्रणाली ही अपना संतुलन खो चुकी है? शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना था, लेकिन वह अब अंकों और रैंक के गणित में सिमट कर रह गया है। ज्ञान से ज़्यादा प्रदर्शन मायने रखता है, और प्रदर्शन से ज़्यादा उसका प्रचार। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भयावह पहलू है बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव। परीक्षा, इंटरव्यू और चयन की अनिश्चितता बच्चे के भीतर डर और असुरक्षा पैदा करती है। असफलता की स्थिति में पहला सवाल यही होता हैकृ"अब क्या होगा?" यह सवाल सिर्फ़ भविष्य का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का भी होता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी असफलता उसके माता–पिता की हार है। यह भाव उसके आत्मविश्वास को गहरे तक चोट पहुँचाता है। विडंबना यह है कि माता–पिता भी इस दबाव के शिकार हैं। समाज ने उनके सामने सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा रख दी हैकृटॉप स्कूल, टॉप कॉलेज और टॉप करियर। वे यह सोचने से डरते हैं कि अगर उनका बच्चा इस तय ढाँचे में फिट नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे। परिणामस्वरूप वे बच्चे की रुचि, क्षमता और स्वभाव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता इस समस्या को और गंभीर बना देती है। जिनके पास संसाधन हैं, वे महँगी कोचिंग, प्राइवेट स्कूल और मैनेजमेंट कोटा खरीद सकते हैं। लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए यह दौड़ कहीं ज़्यादा कठिन है। योग्यता के बावजूद अवसर न मिलना, व्यवस्था पर से भरोसा तोड़ देता है। धीरे–धीरे शिक्षा सामाजिक न्याय का माध्यम न रहकर विशेषाधिकार का प्रतीक बन जाती है। एक और चिंताजनक पहलू यह है कि हम बच्चों को सोचने के बजाय रटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सवाल पूछने वाले बच्चे 'डिस्ट्रैक्टेड' माने जाते हैं और उत्तर याद करने वाले 'मेधावी'। रचनात्मकता, संवेदनशीलता और नैतिकता जैसे गुण पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए हैं। शिक्षा का लक्ष्य इंसान बनाना था, लेकिन हम मशीन तैयार करने में लगे हैं। इस संदर्भ में यह सवाल बेहद ज़रूरी हैकृक्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ टॉपर पैदा करना है? या ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समाज के प्रति ज़िम्मेदार हों, सवाल पूछ सकें और बदलाव ला सकें? जब तक हम इस सवाल का ईमानदारी से उत्तर नहीं खोजेंगे, तब तक दाख़िले की यह दौड़ और ज़्यादा बेरहम होती जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को बाज़ार से मुक्त किया जाए और मूल्यांकन प्रणाली को मानवीय बनाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और अवसरों को समान बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास हों। सबसे ज़रूरी है माता–पिता और समाज की सोच में बदलावकृकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और सफलता का एक ही रास्ता नहीं होता। अगर शिक्षा को आनंद, जिज्ञासा और आत्मविकास का माध्यम बना दिया जाए, तो दाख़िले की यह दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाएगी। वरना हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भविष्य सौंपेंगे, जहाँ डिग्रियाँ तो होंगी, लेकिन संतुलन और संवेदनशीलता नहीं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम रुककर सोचेंकृक्या शिक्षा का मक़सद केवल टॉपर पैदा करना है, या संवेदनशील, सोचने–समझने वाला इंसान बनाना? जब तक दाख़िले की यह अंधी दौड़ जारी रहेगी, तब तक शिक्षा बोझ बनी रहेगी, आनंद नहीं। बदलाव सिस्टम में चाहिए, लेकिन शुरुआत हमारी सोच से होगी–वरना यह दौड़ हर साल और बेरहम होती जाएगी।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

विकसित भारत की उड़ान : बजट 2026 के आर्थिक संकल्प

—ललित गर्ग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवीन केंद्रीय बजट को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न की ठोस आधारशिला के रूप में सामने आता है। यह बजट उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह है जो बीते वर्षों में चली आर्थिक सुधारों की पटरियों पर तेज़ गति से दौड़ते हुए अब भारत को उच्च विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने का दावा करता है। तुलनात्मक, विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती बजटों की निरंतरता को बनाए रखते हुए कई नए आयाम भी जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और भविष्यगामी बनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र यहां नारे से आगे बढ़कर नीतिगत संरचना का रूप लेता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की दृष्टि विशेष रूप से विवेचनात्मक है। चिकित्सा अवसंरचना के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से गांव–गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को केवल खर्च नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश मान रही है। यदि पिछले दशक के बजटों से तुलना की जाए तो स्वास्थ्य पर आवंटन और दृष्टिकोण दोनों में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह बदलाव भारत को न केवल स्वस्थ समाज की ओर ले जाने वाला है, बल्कि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को भी दीर्घकाल में मजबूती देगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट की आत्मा दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़ी शिक्षा पर बल यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य के भारत के लिए आज के युवाओं को तैयार करना चाहती है। पूर्ववर्ती बजटों में शिक्षा पर खर्च की चर्चा होती थी, लेकिन इस बजट में शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ यह बजट तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतीत होता है। विकास की दृष्टि से यह बजट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस समावेशन' का मॉडल प्रस्तुत करता है। रेलवे कॉरिडोरों के विकास, लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, सड़क, बंदरगाह और शहरी अवसंरचना में निवेश को जिस तरह प्राथमिकता दी गई है, वह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सात रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन का माध्यम भी है। यदि इसे पिछले बजटों से जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानकर लगातार गति दे रही है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट विशेष उल्लेख के योग्य है। कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, किसान कल्याण और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े प्रावधान यह संकेत देते हैं कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मंशा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल सुविधाओं, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता सुधरने की संभावना बढ़ती है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संदर्भ में भी बजट का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से व्यापक है। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। गरीबों और वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं इस बजट को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी संतुलित बनाती हैं। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह बजट कल्याण और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, जो किसी भी दीर्घकालिक आर्थिक नीति की अनिवार्य शर्त है। युवाओं के लिए यह बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप, नवाचार, स्किल इंडिया, रोजगार सृजन और नई तकनीकों में निवेश युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यदि इसे आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि बजट में क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक यथार्थ का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि आलोचक इसे चुनावी बजट कह सकते हैं, लेकिन विवेचनात्मक दृष्टि से यह कहना अधिक उचित होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट का जन–आकांक्षाओं से जुड़ा होना स्वाभाविक है, बशर्ते वह दीर्घकालिक विकास को बाधित न करे। इस बजट में दीर्घकालिक दृष्टि और तात्कालिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन दिखाई देता है। समीक्षात्मक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी बजट की सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों के साथ समन्वय और पारदर्शी प्रशासन इस बजट की वास्तविक परीक्षा होंगे। फिर भी, तुलनात्मक दृष्टि से यह बजट भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रतीत होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के विकास की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। यह वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए रास्ता तैयार करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, नारी शक्ति और युवाओं को केंद्र में रखकर यह बजट 'विकसित भारत 2047' की दिशा में एक सशक्त कदम है। यदि इसे निरंतर सुधार, जवाबदेही और समावेशी क्रियान्वयन का साथ मिला, तो यह बजट इतिहास में केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव के रूप में याद किया जाएगा।

राशिफल

मेष :– विचारों की अस्थिरता आपको उलझनपूर्ण परिस्थिति में डालेगी। नौकरी–व्यवसाय के क्षेत्र में स्पर्धायुक्त वातावरण रहेगा। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। प्रवास की संभावना है।

वृषभ :– मन की दुविधा ठोस निर्णय पर आने से रोकेगी जिससे हाथ आए अवसर आप खो देंगे। झक्वी व्यवहार के कारण संघर्ष में उतरने की संभावना है। नए कार्य के लिए दिन अच्छा नहीं है।

मिथुन :– आज का दिन लाभदायक साबित होने की आशा रख सकते हैं। सुबह से ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा। आर्थिक लाभ मिलने के साथ–साथ कहीं से गिफ्ट प्राप्त हो सकता है।

कर्क :– शरीर और मन में बेचौनी और अस्वस्थता का अनुभव होगा। मन की संदिग्धता और दुविधा आपकी निर्णयशक्ति को कसौटी के शिखर पर चढ़ाएंगे। वाद–विवाद से दूर रहें।

सिंह :– आज के दिन आपको विविध लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे समय में मन का ढीलापन आपको लाभ से वंचित न कर दे, इसका ख्याल रखें। पदोन्नति और आय वृद्धि का योग है।

कन्या :– नए कार्य शुरू करने के लिए निर्मित योजनाओं को अमल में लाने का आज उत्तम समय है। व्यापार में लाभ होगा। बकाया वसूली के पैसे वापस मिलेंगे। पिता की तरफ से लाभ होगा।

तुला :– लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक स्थान की मुलाकात होगी। विदेश यात्रा के लिए अनुकूलता रहेगी। फिर भी आपको संतान और स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। धन का खर्च होगा।

वृश्चिक :– आज का दिन सावधानीपूर्वक बिताएं। नए कार्य शुरू न करें। क्रोध, आवेश और अनैतिक आचरण आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। दुर्घटना से बचें।

धनु रू बौद्धिक, तार्किक, विचार–विनिमय और लेखन कार्य के लिए शुभ दिन है। भागीदारी में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ के सम्बंधों में अधिक घनिष्ठता रहेगी। मान–सम्मान मिलेगा।

मकर :– आज से आपके व्यापार–धंधे का विकास होगा। आर्थिक रूप से लाभदायक दिन होने से पैसे की लेन–देन में सरलता रहेगी। परिवार में सुख– शांति का माहौल रहेगा।

कुंभ :– आज आप संतान और अपने स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंतित रहेंगे। अपच, पेट–दर्द से परेशान होंगे। विचारों में तेजी से परिवर्तन मानसिक स्थिरता में खलल पहुंचाएगा।

मीन :– शारीरिक– मानसिक भय रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ वाद–विवाद होगा। माताजी का स्वास्थ्य खराब होगा। अनचाही घटनाओं से आपके उत्साह में कमी आएगी। अनिद्रा से परेशान रहेंगे।

कमजोरों के लिए खतरनाक रसूखदार लोग

अमेरिका के कुख्यात नाबालिग लड़कियों के यौन तस्कर जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी लाखों फाइलें अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी की हैं। शुक्रवार को 30 लाख पेज, एक लाख 80 हजार तस्वीरें और दो हजार वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट किए गए। इन नए खुलासों में ऐसे घिनौने और भयानक अपराध सामने आए हैं, जिन्हें देखकर साधारण इंसान की रूह कांप जाए। ज्यादा डरावनी बात ये है कि एपस्टीन के साथ दुनिया भर के ऐसे नामी–गिरामी और रसूखदार लोगों के नाम जुड़े हैं, जो खुद को लोकतंत्र, उदारवाद, मानवाधिकारों के पैरोकार के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। मगर हकीकत में वे कमजोर लड़कियों और बच्चों पर पैशाचिक अत्याचार करते हैं। सोशल मीडिया पर 2009 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गैब्रिएला रिको जिमेनेज नाम की मैक्सिकन मॉडल मैक्सिको के मॉन्टेरी में फिएस्टा के बाहर खड़ी होकर चिल्ला–चिल्लाकर बता रही है कि वह जैफ्री एपस्टिन से जुड़े एक मॉडलिंग आयोजन में गई थी जहां दुनियाभर के नेता और बिजनेसमैन पार्टी कर रहे थे और वो लोग श्बच्चों के मांसश खा रहे थे। संभवतरू यह पहली बार था जब किसी ने एपिस्टन या उसके निजी द्वीपों पर हो रहे बच्चियों के बलात्कार और हत्या के आरोप लगाए थे। लेकिन पुलिस ने इस लड़की को मनोरोग का शिकार बताकर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यह लड़की कभी नहीं दिखी। अब उस घटना के 17 साल बाद एपिस्टीन फाइलें जारी हुई तो पता चला यह लड़की जो कुछ बोल रही थी, वो पागलपन नहीं था। बल्कि उसमें काफी हद तक हकीकत भी थी। क्योंकि अब एपस्टीन और उनके तथाकथित बड़े ग्राहकों का शिकार कुछ लड़कियों ने सामने आकर हकीकत बयां की हैं। किसी ने बताया कि 10 साल की अबोध उम्र में उनके साथ दिन में तीन–तीन बार बलात्कार हुआ, तो किसी ने बताया कि कैसे पार्टियों के बहाने अमीर लोगों के सामने उन्हें पेश किया गया। बिल गेट्स की पत्नी रही मेलिंडा गेट्स ने भी एक साक्षात्कार में बताया है कि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि बिल गेट्स एपस्टीन से मिलते थे। खुद मेलिंगा गेट्स केवल एक बार एपस्टीन से मिलीं और उन्हें काफी अफसोस हुआ कि उन्होंने यह मुलाकात की। मेलिंडा गेट्स ने एपस्टीन को घृणित और बुराई का साक्षात रूप बताया और कहा कि उस मुलाकात के बाद उन्हें बुरे सपने आते थे।बिल गेट्स से उनके तलाक के कारणों में एक वजह एपस्टीन से बिल गेट्स के संबंध भी थे। न्याय विभाग द्वारा जारी एपस्टिन फाइलों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र भी सैकड़ों बार किया गया है। ट्रंप की एपस्टीन से दोस्ती थी। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि यह कई साल पहले खराब हो गई थी और उन्होंने एपस्टीन के यौन अपराधों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भी कई पुराने वीडियो आए हैं, जो नैतिकता के मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं। अब भले ही एपस्टिन से उनकी दोस्ती बरसों पहले खराब हो चुकी हो, लेकिन बेहतर यही होता कि ट्रंप अपने पद से इस्तीफा देकर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए निष्पक्ष जांच का मौका दें। ध्यान रहे कि 10 अगस्त 2019 को एपस्टिन की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इसमें हत्या की साजिश देखी जा रही है। क्योंकि एपस्टिन अगर दोषी पाया जाता तो उससे जुड़े कई बड़े नामों पर भी आंच आ सकती थी। अभी के खुलासे के बाद भी कुछ बड़ी हस्तियों ने या तो माफी मांगी है या अपने पद से इस्तीफा दिया है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे–मैरिट ने एपस्टीन के साथ अपनी शर्मनाकश दोस्ती के लिए माफी मांगी है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने भी कहा है कि क्राउन प्रिंसेस ने गलत जजमेंट किया था। वहीं किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू का नाम भी आया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग में गवाही देने आना चाहिए। स्लोवाकिया सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एप्सटीन से अपने संबंधों के सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। पीटर मैंडेलसन को पिछले साल एपस्टीन के साथ संबंधों के कारण वाशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत के पद से हटा दिया गया था। अब उन्होंने रविवार को लेबर पार्टी छोड़ दी। अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम भी आया है। जिसमें बताया गया है कि जेफ्री एपस्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा...भारतीय पीएम मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाया। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे। ये काम कर गया। इसी पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि– श्याद रहे– पीएम मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके तीन दिन बाद एपस्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25–26 जून 2017 को मोदी, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफ्री एपस्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़ें तो समझ आता है कि मोदी, जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एपस्टीन से सलाह ली। इसके एक हफ्ते बाद (4 से 6 जुलाई 2017) मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक– वहां नाचे और गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफ्री एपस्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने तीन सवाल करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी, जेफ्री एपस्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे? मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? एपस्टीन ने लिखा है– इट वर्क्ड.. तो इसका क्या मतलब है? हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नरेंद्र मोदी और जेफ्री एपस्टीन की मुलाकात के दावों को खारिज किया है।

क्या ट्रम्प विश्व युध्द के भयंकर परिणामों से परिचित हैं ?

मोहन लाल

ट्रम्प की 'बाडी–लैंग्वेज' से तो नहीं लगता कि उन्हें युद्ध के भयानक परिणामों का ज्ञान हो। यह तो ठीक है कि अमरीका की 'राजनीतिक–दादागिरी' सब देशों पर भारी है लेकिन विश्व के राजनेता उन देशों की लिस्ट तो निकाल कर पढ़ें जिन्हें अमरीका की दादागिरी ने तबाह कर दिया। अमरीका की विस्तारवादी राजनीति आज दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की ओर धकेल रही है। वेनेजुएला, जो एक 'प्रभुसत्ता–सम्पन्न' राष्ट्र है, उसके राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को हाथों–पैरों में बेडियां डाल कर अमरीका की खतरनाक जेल में बंद कर देना, एक घृणित दादागिरी है। भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया कि भारत अपनी तेल आपूर्ति के लिए, रूस से पैट्रोल–डीजल खरीद रहा है। एक अन्य देश 'ग्रीनलैंड' पर इसलिए अमरीका अपना कब्जा जमाना चाहता है क्योंकि 'ग्रीनलैंड' की सीमा अमरीका से लगती है। तेल की खातिर ईरान में आग लगा रखी है। आज तक 2500 लोग ईरान के इन दंगों में अपनी जान गंवा चुके हैं। अमरीका ईरान में उपद्रवियों की पीठ थपथपा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का ताली बजाना, दोनों मुट्ठियों को बंद कर हवा में लहराना यही इंगित करता है कि आज दुनिया में कोई अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीका थानेदार है और दुनिया को उसका हुक्म मानना ही होगा। जो नहीं मानेगा, उस देश का हाल 'वेनेजुएला' जैसा होगा। अमरीका ने अपनी तेल की भूख मिटाने के लिए रूस–यूक्रेन युद्ध में घी डाल रखा है। दुनिया सुन रही है कि ट्रम्प 'रूस–यूक्रेन' युद्ध को समाप्त करने के लिए 'मध्यस्थ' की भूमिका निभा रहे हैं लेकिन ट्रम्प 'रूस–यूक्रेन' युद्ध को समाप्त क्यों करवाएंगे? ट्रम्प भारत के विरुद्ध बंगलादेश और पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहे हैं। पाकिस्तान के 'फील्ड–मार्शल' मुनीर को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज दे रहे हैं। तीनों देशों–भारत बंगलादेश और पाकिस्तान को एक–दूसरे से लड़ाने की योजना बना रहे हैं। यहीं बस नहीं, अमरीका ने झूठे आरोप लगा कर कि ईराक ने 'रासायनिक–औजार' छिपा रखे हैं, ईराक के लोकप्रिय नेता निरपराध सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया था। लिबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी को सन्देहास्पद परिस्थितियों में मार दिया गया। अमरीका ने सोमालिया, सीरिया, फिलिस्तीन में 'गाजा–पट्टी' क्षेत्र को कब्रगाह बना दिया। इसराईल और हिजबुल्ला से सन्धि ही नहीं होने दी। पाठकवृंद, क्या आप जानते हैं कि 2025–26 में अमरीका का 'रक्षा–बजट' 895 अरब डालर है जिसके बल पर अमरीका 'मेमने' की तरह कभी भी किसी भी देश को झूठे इल्जाम लगा कर हड़प सकता है? अमरीका ने वियतनाम से लड़ाई लड़ी, अफगानिस्तान में वर्षों तालिबानों से युद्ध किया परन्तु दोनों देशों में उसकी शर्मनाक हार हुई।

योगी सरकार के नेतृत्व में रेशम उद्योग को मिली नई पहचान

सिल्क एक्सपो का शुभारंभ, मंत्री राकेश सचान ने किया उद्घाटन

16 विशिष्ट जन सम्मानित,रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन

संवाददाता

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, बाजार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में सिल्क एक्सपो–2026 का उद्घाटन किया। मंत्री राकेश सचान ने पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप की उपस्थिति में पं दीन दयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान का वितरण किया तथा रेशम मित्र 2025 पत्रिका का विमोचन किया। मंत्रीगणों ने प्रदर्शनी में लगाए गए सजीव प्रदर्शनों एवं रेशमी उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए विभागीय प्रयासों की सराहना की। राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में रेशम उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस और परिणामोन्मुखी कार्य किए गए हैं। वर्ष 1988 में रेशम विभाग की स्थापना के समय प्रदेश में मात्र 27 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर लगभग 450 से 500 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है। वर्ष 2022 में उत्पादन लगभग 300 मीट्रिक टन था, जिसे बीते चार वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 50 मीट्रिक टन की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रेशम की वार्षिक खपत लगभग 5 से 6 हजार मीट्रिक टन है, जिसमें अकेले वाराणसी एवं आसपास के क्षेत्रों में ही 3500 से 4000 मीट्रिक टन रेशम की खपत होती है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुरूप रेशम उत्पादन कर आत्मनिर्भर बने, जिससे किसानों, बुनकरों और उद्यमियों को स्थायी रोजगार और आय के अवसर मिल सकें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत कुशीनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बस्ती, औरैया एवं सहारनपुर सहित विभिन्न जनपदों में नई मल्टी रीलिंग इकाइयों की स्थापना की गई है। वर्ष 2024–25 में 1630 लाभार्थियों को कीटपालक गृह निर्माण एवं उपकरण क्रय हेतु 32.49 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई, जबकि

वाराणसी में रेशम वस्त्रों की बुनाई, रंगाई एवं वस्त्र निर्माण हेतु 75 इकाइयों को 2.16 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1100 नए लाभार्थियों को रेशम उत्पादन से जोड़ने के लिए 18.10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें जनजाति वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत 10 वर्षों में 13,500 किसानों को 9,000 एकड़ भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण से जोड़ते हुए 360 मीट्रिक टन अतिरिक्त रेशम धागा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों और उद्यमियों की सुविधा के लिए रेशम मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, मॉनिटरिंग एवं पारदर्शी क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का चयन और योजनाओं का क्रियान्वयन सरल एवं प्रभावी हुआ है। राज्य मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 2000 से 2500 नए किसानों को रेशम कीटपालन से जोड़कर उत्पादन, रोजगार और आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। रेशम उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।सिल्क एक्सपो अंतर्गत आयोजित पं दीन दयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान समारोह में रेशम उद्योग से जुड़े कृषकों, बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों एवं कार्मिकों को 8 श्रेणियों में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 16 विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपये की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए।सिल्क एक्सपो में केंद्रीय रेशम बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत उत्तर प्रदेश सहित बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों के बुनकरों एवं व्यापारियों द्वारा शुद्ध रेशमी उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 6 फरवरी तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।

महोबा मंत्री–विधायक विवाद पर पंकज चौधरी बोले, पार्टी ने लिया है मामले का संज्ञान

संवाददाता

लखनऊ। महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा मामला पार्टी के संज्ञान में है। इस मामले में दोनों नेताओं से बात कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। वहीं, केंद्रीय बजट 2026–27 पर प्रतिक्रिया देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय लेखा–जोखा नहीं, बल्कि देश के भविष्य का स्पष्ट विजन है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस समावेशी विकास पर है और यह बजट विकास का एक मजबूत ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसमें सात नई हाई–स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिनका सीधा फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्लोबल बायो–फार्मा, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों पर

विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में देश को आगे ले जाने की कवायद की जा रही है। पंकज चौधरी ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र में भी पहले की तुलना में अधिक बजट आवंटन किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट पुराने वर्षों से चली आ रही जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ–साथ नए विजन के साथ देश को विकास की नई दिशा देने वाला है। वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव स्वयं अपने बयानों को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं। उन्होंने पहले ही इस विषय पर बयान दे दिया है और अब बार–बार अलग–अलग बातें कर रहे हैं।

यूजीसी के सपोर्ट में छात्रों का हंगामा : पुलिस ने आंदोलनकारीयों को खींचकर बस में भरा

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में मंगलवार को बिरसा आंबेडकर फुले छात्र संगठन (बापसा) उत्तर प्रदेश के बैनर तले यूजीसी गाइडलाइंस–2026 के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर एकत्रित हुए। गेट नंबर–3 से परिवर्तन चौक तक समर्थन मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक छात्रों को दौड़ाया। इस बीच दूसरी तरफ से छात्र परिवर्तन चौक पहुंच गए। वहां पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें टांग–टांगकर बस में बैठाकर ले गई। बापसा उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया ने कहा 2 दिन पहले यहां यूजीसी के नए गाइडलाइंस के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। बाहरी गुंडे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब धारा 144 नहीं लागू थी। अब धारा 144 लागू कर दी गई है। हम अपना प्रदर्शन करेंगे। कई जिलों से लोग आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरीके से लागू किया जाए। बिरसा आंबेडकर फुले छात्र संगठन का कहना है कि जब तक यूजीसी गाइडलाइंस को पूरी तरह लागू नहीं किया जाएगा।

समुचित जानकारी के अभाव में तत्काल कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पर बोलीं मायावती

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारत और अमेरिका के बीच बीच हुए समझौते के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाली वस्तुओं पर जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसे लेकर मायावती ने एक पर पोस्ट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अनेक शर्तों के साथ आपसी समझौते के बाद अमेरिका द्वारा 18 प्रतिशत टैरिफ लगाये जाने की खबर कितनी देश व जनहित में है इसके सम्बन्ध में समुचित जानकारी के अभाव में तत्काल कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि इसपर जमीनी अमल होने के बाद ही यह सही से मालूम हो पायेगा कि इससे देश के खासकर बहुजनों, गरीबों, मजदूरों, किसानों व महिलाओं आदि का क्या भला होगा। मायावती ने कहा कि वैसे तो यह बेहतर होता कि इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा संसद के सत्र के दौरान् ही इसके बारे में विस्तार से बताया जाता ताकि लोगों को सही–सही जानकारी मिल पाती। आप को बता दें कि भारत

और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाली वस्तुओं पर जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता में यह सफलता ऐसे वक्त में मिली है, जब भारतीय उद्योग उच्च अमेरिकी शुल्क के कारण तनाव में थे।

उन्होंने कहा, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एकल निर्यात बाजार है और बेहतर व्यापारिक शर्तें अमेरिकी बाजार में भारतीय परिधान उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर रुद्र कुमार पांडेय ने कहा कि अमेरिका का फैसला दोनों पक्षों के रणनीतिक इरादों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के निर्यात–प्रतिस्पर्धी रुख को पुख्ता करता है और ऐसे समय में आया है जब अमेरिका अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से दूर ले जा रहा है। पांडेय ने कहा, इस फैसले का तत्काल लाभ शुल्क संवेदनशील और श्रम–प्रधान क्षेत्रों को मिलेगा। कपड़ा, परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो घटक इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र अमेरिकी बाजार में वियतनाम और बांग्लादेश के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि इससे उन ऑर्डरों के तुरंत जारी होने की उम्मीद है, जिन्हें पहले रोक दिया गया था। विशेष रूप से परिधान, कपड़ा और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा।

ट्रेड डील पर सपा प्रमुख अखिलेश का हमला, सीड बिल खतरनाक, किसानों के हितों से खिलवाड़

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर किसानों के हितों से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के लिए खोलना देश की खेती–किसानी पर निर्भर लगभग 70 प्रतिशत आबादी के साथ सीधा धोखा है। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाली भाजपा जनता को बताए कि देश की अर्थव्यवस्था से समझौता

कर उन्होंने कितना कमीशन लिया है। इस फैसले से केवल किसान ही नहीं, बल्कि निम्न मध्यवर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों में मुनाफाखोरी बढ़ेगी तथा बिचौलियों की नई जमात पैदा होगी, जिससे रोजमर्रा की चीजें और महंगी होंगी। उन्होंने आशंका जताई कि विदेशी कंपनियों के प्रवेश से धीरे–धीरे किसानों की आय घटेगी और वे मजबूर होकर अपनी जमीन बड़े पूंजीपतियों व कारपोरेट घरानों को बेचने पर विवश होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जमीनों पर कब्जा करना ही भाजपा और उसके सहयोगियों का अंतिम मकसद है। अखिलेश यादव ने प्रस्तावित सीड बिल को भारतीय खेती के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि यह उसी किसान–विरोधी सोच की उपज है जिसने भू–अधिग्रहण जैसे कानून लाए और खाद के लिए किसानों को लाइन में लगाकर अपमानित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बीज कंपनियों से, फिर पेस्टीसाइड कंपनियों से, साइलो निर्माण, फसल बीमा, न्यूनतम कीमत तय करने और फसल खरीद–फरोख्त तक हर स्तर पर कमीशनखोरी की जाएगी, जिससे भारतीय परिस्थितियों में खेती पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है।

छात्राओं को दिव्यांगजनों, पिछड़े और आरक्षित छात्रों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी

संवाददाता

लखनऊ। नवयुग कन्या महाविद्यालय के विकलांग विद्यार्थियों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (एस ई डी जी एस) पर बने सेल एवं बी एड विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन और अन्य वंचित समूह के लिए सरकारी नीतियां विषय पर प्रख्यात वक्ता जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित की व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के माध्यम से छात्राओं को, दिव्यांगजनों,अन्य पिछड़े और आरक्षित छात्रों के लिए सरकार (यूपी और केंद्र) द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और नीतियों(पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना,शुल्क प्रतिपूर्ति

योजना,शादी अनुदान योजना,कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना,छात्रावास निर्माण योजना,मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ,दिव्यांग पेंशन योजना,कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना आदि)के बारे में जागरूक किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने अतिथि का स्वागत और अभिनंदन किया और भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया अतिथि का स्वागत बीएड विभाग की प्रोफेसर रशीदा खातून ने किया। कार्यक्रम का संचालन मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने सुचारू रूप से किया। कार्यक्रम को सफल एवं उपयोगी बनाने में रसायन विज्ञान विभाग की डॉक्टर ममता वर्मा, जंतु विज्ञान विभाग की विमला बिन्द, वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉक्टर स्नेहा चौधरी का विशेष योगदान रहा। अंत में बीएड विभाग की प्रोफेसर सरिता कनौजिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बी० एड० विभाग की प्रवक्ता प्रोफेसर निशी गुप्ता एवं डॉ मनीषा बड़ौनियाँ एवं महाविद्यालय की प्रवक्ताओं और छात्राओं की उपस्थित सराहनीय रही।

2027 चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी, 15 दिनों में हो सकते बड़े बदलाव

बीजेपी आ रही चुनावी मोड में

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मोर्चों की टीम बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक

15 दिन के भीतर पार्टी में बदलाव होने की संभावना है।एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। बीजेपी में जल्द ही अनुसूचित जाति मोर्चे, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य मोर्चो के अध्यक्ष समेत टीम में बदलाव की संभावना है। इसी माह ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मोर्चों में बदलाव होने के बाद पार्टी चुनावी मोड में जुट जाएगी। बीजेपी के मोर्चों के बदलाव में जातीय समीकरण का साधने पर जोर दिया जा सकता है।बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कुर्मी समाज से आते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट, ब्रज में यादव और ब्राह्मणों को समीकरण देखने को मिल सकता हैं। सपा के पीडीए की काट की भी झलक बदलाव में दिखाई दे सकती है। यूपी बीजेपी की ये कवायद आगामी पंचायत चुनाव, विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है ताकि पार्टी का प्रदर्शन और मजबूत हो सके और यूपी में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई जा सके. सूत्रों के मुताबिक इन मोर्चों में 30–40 फीसद तक फेरबदल हो सकता है। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक हो चुकी हैं,जिसमें पार्टी क प्रकोष्ट, विभागों के अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए थे।पंकज चौधरी ने इस बैठक के बाद कहा था कि पार्टी के विभिन्न विभाग और प्रकोष्ठों में काम करने वाले पदाधिकारियों को भूमिका काफी अहम होती है। संगठन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों तक पार्टी की कार्यशैली और नीतियों की जानकारी पहुंचाने में इन मोर्चों को अहम भूमिका होता है। विभिन्न संगठन के लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं और पार्टी मजबूत होती है।

विधायक राजेश्वर पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका-जूते मारे

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी फोटो को जूते मारे और पैरों से कुचला। राय ने भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह पर अभद्र टिप्पणी की थी। भाजपा नेता शिव शंकर सिंह शंकरी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता कानपुर रोड स्थित शहीद पथ तिराहे पर जमा हुए। यहां कार्यकर्ताओं ने अजय राय का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय राय की टिप्पणी को निराधार, आपत्तिजनक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अजय राय ने अपने बयान में विधायक पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में रहते हुए देश और प्रदेश को लूटने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, इन आरोपों के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न केवल एक जनप्रतिनिधि की छवि को धूमिल करने का प्रयास हैं, बल्कि ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासनिक सेवाओं का भी अपमान है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपने पूरे सेवाकाल में ईमानदारी और कानून के दायरे में रहकर कार्य किया है। इस प्रदर्शन के कारण कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात बाधित हुआ। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी दूसरी पटरी पर चले गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।बाद में एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद करीब एक बजे यातायात पूरी तरह सुचारु हो सका। इस दौरान शिव शंकर सिंह शंकरी की ओर से सरोजनी नगर थाने में अजय राय के खिलाफ तहरीर भी दी गई। तहरीर में विधायक के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बीते रविवार को सरोजनी नगर में कांग्रेस के संविधान संवाद महापंचायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरोजनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह पर ईडी में रहकर देश व प्रदेश लूटने का आरोप लगाया था।

सिर कूचकर युवक की हत्या, सड़क किनारे शव मिला, खून से सनी ईंट बरामद

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के मुल्ला खेड़ा गांव के पास मंगलवार सुबह सड़क किनारे एक मजदूर का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान ग्राम चौरासी निवासी संतराम (40) पुत्र दुलारे रावत के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि ईंट से वार कर हत्या की गई है। ग्रामीणों के अनुसार सुबह सड़क किनारे शव पड़ा देख ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। सुबह 8.27 बजे प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की जांच के दौरान एक ईंट बरामद की गई है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया जाना माना जा रहा है। पुलिस ने मौके को सील कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। फुटेज में मृतक साइकिल से शराब के ठेके की ओर जाता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस इसी रूट के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी है। यह जानने की कोशिश कर रही है कि अंतिम बार वह किसके संपर्क में था। पूछताछ में सामने आया कि संतराम मजदूरी कर परिवार का पालन–पोषण करता था।

संक्षिप्त

उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर में बनेगा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब-जेपी नड्डा

संवाददाता

लखनऊ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला प्रमुख राज्य बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस उद्यमिता और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक है। ललितपुर में विकसित हो रहा बल्क ड्रग फार्मा पार्क, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क और राज्य की फार्मास्यूटिकल नीति–2023, उत्तर प्रदेश को विश्वसनीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण के कारण यूपी फार्मा निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। केंद्र की नीतिगत दृष्टि और उत्तर प्रदेश सरकार के जमीनी प्रयास प्रदेश को फार्मा और बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

पत्नी से विवाद में युवक ने फांसी लगाई

संवाददाता

लखनऊ। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गनेशखेड़ा गांव में मंगलवार को एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। ग्रामीणों ने गांव के बाहर खेत में दुपट्टे के फंदे से लटकता शव देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान सुभाष चंद्र (40) पुत्र छोटेलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को पेड़ से उतरवाया। मृतक के भाई फूलचंद की उपस्थिति में निजी वाहन से सीएचसी मोहनलालगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस आशंका जता रही है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।

अज्ञात वाहन ने बेटी की बर्थडे पार्टी से लौट रहे दिव्यांग को रौंदा

संवाददाता

लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 35 वर्षीय कुन्जन गौतम की मौत हो गई। जुनाबगंज तिराहे के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई। कुन्जन गौतम सोमवार रात करीब 11:30 बजे अपने घर खसरवारा लौट रहे थे। जुनाबगंज तिराहे के पास बनी–मोहन लाल गंज रोड पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक कुन्जन के ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए मौके से फरार हो गया।

कौशल उन्नयन से जोड़कर युवाओं को बनाएं आत्मनिर्भर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की समीक्षा

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि वे युवाओं को अधिक से अधिक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। साय ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नए–नए उद्योग स्थापित होने वाले हैं, इन उद्योगों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज महानदी भवन मंत्रालय में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समय–समय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले का आयोजन करें। बैठक में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मुख्य सचिव विकासशील सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने और तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईटीआई के आधुनिकीकरण से युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने सीएसएसडीए एवं राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी के एकीकरण के प्रस्ताव पर सहमति दी और शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलों में सहायक निदेशक एवं सहायक परियोजना अधिकारियों की युक्तियुक्त पदस्थापना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षित युवाओं से फीडबैक हेतु विकसित Trainee Feedback मॉड्यूल को और सशक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013 से अब तक 4 लाख 90 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 71 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में राज्य में 356 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाएं (वीटीपी) एवं 207 पंजीकृत कोर्स संचालित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत राज्य में हब–एंड–स्पोक मॉडल पर 6 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से आईटीआई के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत तथा उद्योगों की हिस्सेदारी न्यूनतम 17 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत 9 जिलों में लगभग 1,700 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास हेतु बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर सहित जिलों में 600 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा गया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–26 में गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, विभागीय सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, उद्योग सचिव रजत कुमार, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक तकनीकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण विजय दयाराम के., स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरूण अरोरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भारत से हारने का डर, इसलिए बॉयकॉट का बहाना? मैच से पहले ही PAK का गेम ओवर!

एजेंसी

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2026 को शुरू होने में अब बस चार दिन का वक्त रह गया है। सात फरवरी से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान का ड्रामा चालू हो गया है। टूर्नामेंट के बहिष्कार की गीदड़भभकी से शुरू हुआ ड्रामा अब भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बहिष्कार पर आकर रुक गया है। भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। साथ ही 21वीं सदी में पाकिस्तान का आईसीसी टूर्नामेंट्स भी भारत के खिलाफ रिकॉर्ड यह बताता है कि पड़ोसी मुल्का का भारत से खेलने का डर जायज है। भारत के खिलाफ लगातार हार से डरा पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ लगातार हार ने उन्हें डरा दिया है और यही वजह है कि उसने बॉयकॉट का रास्ता अपनाया। अगर मैच ही नहीं होगा तो उनकी अपने मुल्क में थू–थू नहीं होगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर संजय मांजरेकर के हालिया वीडियो ने भारत–पाकिस्तान क्रिकेट बहस को फिर से गर्म कर दिया है। वीडियो में मांजरेकर का साफ कहना है कि अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने से कतरा रहा है, और इसकी वजह कोई राजनीति नहीं बल्कि खेल का डर है। मांजरेकर के शब्दों में, सच्चाई ये है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हराना अब उनके लिए असाधारण चुनौती बन चुका है। भारत के खिलाफ मैच से बचने या बॉयकॉट की बात करना दर्शाता है कि पाकिस्तान खेल के मैदान में जवाब देने के बजाय बहाने तलाश रहा है। मांजरेकर ने महामुकाबले पर सवाल खड़े किए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले को वर्षों से महामुकाबला कहा जाता रहा है, लेकिन मांजरेकर ने इस धारणा पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। मांजरेकर का कहना है कि अगर भारत–पाकिस्तान मैच नहीं भी होता है, तो इससे न टूर्नामेंट की वैल्यू घटती है और न ही भारतीय क्रिकेट को कोई नुकसान होता है। मांजरेकर के शब्दों में, अगर भारत–पाकिस्तान मैच नहीं होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सच कहूं तो काफी समय से असली मैच, मैच से पहले होने वाले हाइप और ड्रामे के आसपास भी नहीं पहुंच पाता। भारत और पाकिस्तान अब क्रिकेट में एक स्तर पर नहीं मांजरेकर का सबसे तीखा हमला इसी बिंदु पर है। उन्होंने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान अब क्रिकेट के एक ही स्तर पर नहीं हैं। उन्होंने कहा, श्इसका कारण बिल्कुल साफ है। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर अब एक ही स्तर पर नहीं हैं। 90 के दशक में और उससे पहले दोनों के बीच क्रिकेट में मुकाबला मजेदार होता था, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत टीम हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं।श यह बयान भावनात्मक नहीं, बल्कि आंकड़ों और मौजूदा हालात पर आधारित नजर आता है। भारत की जीत अब आदत सी लगती है संजय मांजरेकर ने अपने बयान में सबसे चर्चित तुलना भी की। उन्होंने कहा, आज जब भारत पाकिस्तान को हराता है, तो ऐसा लगता है जैसे भारत किसी कमजोर टीम को हरा रहा हो।श यह बात भले ही पाकिस्तान समर्थकों को चुभे, लेकिन पिछले दो दशकों के आईसीसी टूर्नामेंट रिकॉर्ड इस सोच को मजबूत करते हैं। वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और चौंपियंस ट्रॉफी, तीनों बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद एकतरफा रहा है। टी20 और वनडे, दोनों तरह के विश्व कप को मिलाकर भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 15–1 का है। टीम इंडिया को एकमात्र हार 2021 टी20 विश्व कप में मिली थी। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान भारत को कभी नहीं हरा सका है और हमेशा मुंह की खाई है। साल 2001 से अब तक, दोनों टीमों के बीच नडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और चौंपियंस ट्रॉफी को मिलाकर 19 मुकाबले खेले गए हैं।

टी20 विश्वकप में कितनी बार भारतीय खिलाड़ी बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कितने फाइनल में बने हीरो ?

एजेंसी

नई दिल्ली। आईसीसी टी20 विश्वकप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। पहला संस्करण दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। तब से साल 2024 तक नौ संस्करण खेले जा चुके हैं। देखते ही देखते यह टूर्नामेंट क्रिकेट की दुनिया का सबसे रोमांचक और लोकप्रिय फॉर्मेट बन गया। छोटे ओवर, तेज रफ्तार और हर गेंद पर बदलता मैच का रुख, यही टी20 की पहचान है। भारत उन चुनिंदा टीमों में शामिल रहा है, जिसने इस फॉर्मेट में न सिर्फ खिताब जीते बल्कि व्यक्तिगत उपलब्धियों में भी गहरी छाप छोड़ी। टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत सात फरवरी से होने जा रही है। यह टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण होगा। भारत ने अब तक 2007 और 2024 में, यानी दो बार टी20 विश्वकप का खिताब अपने नाम किया है। 2024 में वेस्टइंडीज में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर भारत ने 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी सूखा भी खत्म किया था। कितनी बार भारतीय बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? टी20 विश्वकप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंटका अवॉर्ड पूरे टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस मामले में भारतीय खिलाड़ी सबसे आगे रहे हैं। अब तक तीन बार भारतीय खिलाड़ियों ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है:

विराट कोहली– 2014
विराट कोहली– 2016
जसप्रीत बुमराह– 2024

किस देश के खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने

देश	प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
भारत	3 बार
ऑस्ट्रेलिया	2 बार
इंग्लैंड	2 बार
पाकिस्तान	1 बार
श्रीलंका	1 बार

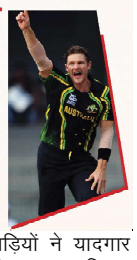

विराट कोहली टी20 विश्वकप इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने का गौरव हासिल किया। 2014 में उन्होंने भारत को लगभग अकेले दम पर फाइनल तक पहुंचाया, जबकि 2016 में उनकी कई बेहतरीन पारियों की बदौलत भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था। हालांकि, सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से हारकर टीम इंडिया बाहर हो गई थी। वहीं 2024 में जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी से पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजों को नाच नचा दिया।

टी20 विश्वकप फाइनल में भारत के हीरो 2007 में इरफान पठान ने की थी घातक गेंदबाजी भारत जब–जब टी20 विश्वकप फाइनल में पहुंचा, वहां कुछ खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले टी20 विश्वकप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। उस मुकाबले में इरफान पठान को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

बाघ, जंगल और पर्यटन का संगम : 8 फरवरी को अलवर टाइगर इंटरनेशनल हॉफ मैराथन

–दौड़ जो बदलेगी सोच : अलवर में टाइगर इंटरनेशनल हॉफ मैराथन
– 35 देशों के धावकों संग अलवर बनेगा पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक मंच

बीएनई

देहरादून /अलवर। अलवर में अलवर टाइगर इंटरनेशनल हॉफ मैराथन (एटीएम–2026) का आयोजन आगामी 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय मैराथन के ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता रणदीप हुड्डा होंगे, जो आयोजन के दौरान अलवर में उपस्थित रहेंगे। मैराथन में केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, बहरीन, तंज़ानिया और इथियोपिया सहित विभिन्न देशों से आए 35 अंतरराष्ट्रीय धावक भाग लेंगे। इनके साथ देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लगभग 18 हजार धावक अलवर की सड़कों पर दौड़ते हुए बाघ संरक्षण, वन सुरक्षा और जिम्मेदार पर्यटन का संदेश वैश्विक स्तर तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा इस मैराथन में करीब 400 दिव्यांगजन भी सहभागिता करेंगे। आयोजन के अवसर पर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा तथा पर्यटन विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया जा रहा है।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के अनुसार अलवर टाइगर मैराथन केवल खेल आयोजन नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता और पर्यटन संवर्धन का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को प्रकृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। मूवमेंट और पर्यावरण संरक्षण की राष्ट्रीय सोच को ज़मीनी स्तर पर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अलवर टाइगर इंटरनेशनल हॉफ मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मैराथन उस विज़न को आगे बढ़ाती है, जिसमें स्वस्थ नागरिक, सुरक्षित पर्यावरण, सतत विकास और जिम्मेदार पर्यटन को एक–दूसरे का पूरक माना गया है। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा के अनुसार अलवर टाइगर मैराथन पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। ब्रांड एंबेसडर और बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने कहा कि अलवर टाइगर हाफ मैराथन से जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमेशा से उनकी व्यक्तिगत सोच का हिस्सा रहा है और यह आयोजन उसी लक्ष्य को मजबूती प्रदान करता है। अलवर हाफ टाइगर मैराथन को अलवर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इको–टूरिज्म, वाइल्डलाइफ टूरिज्म और स्पोर्ट्स टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। सरिस्का टाइगर रिज़र्व, अरावली की प्राकृतिक विरासत और अलवर की सांस्कृतिक पहचान को इस आयोजन के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इससे स्थानीय पर्यटन, होटल उद्योग, गाइड सेवाओं और अन्य संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ स्थानीय आजीविका को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। फिट इंडिया विज़न के अनुरूप आयोजित इस मैराथन में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन, 5 किलोमीटर शक्ति रन और 2 किलोमीटर पैरा रन शामिल हैं। इसमें युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन समान रूप से भाग लेंगे, जिससे यह आयोजन सामाजिक समावेशन का सशक्त उदाहरण बनेगा। अलवर टाइगर मैराथन के माध्यम से यह संदेश एक बार फिर गूंजेगा कि बाघ सुरक्षित रहेगा तो जंगल सुरक्षित रहेंगे, और जंगल सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण, पर्यटन और भविष्यकृतीनों सुरक्षित रहेंगे।

भारत–अमेरिका आर्थिक साझेदारी से उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई उड़ान

टैरिफ में की गई ऐतिहासिक कटौती सीएम योगी के +1 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन को देगी मजबूती एमएसएमई, डिफेंस, फार्मा और टेक सेक्टर में निवेश के लिए खुलेगी राह

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में संपन्न हुई आर्थिक साझेदारी और अमेरिकी टैरिफ में की गई कटौती ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं को नई दिशा दे दी है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लागू टैरिफ को पहले के लगभग 50 प्रतिशत स्तर से घटाकर औसतन 18 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और दृढ़ नेतृत्व का परिणाम है, जिसमें भारत ने अपनी नीतियों पर अडिग रहते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ समानता के आधार पर संवाद किया।

वैश्विक भरोसे की कसौटी पर खरा उतरा भारत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मा कॉन्क्लेव में स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2014 से पहले जिस भारत को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, आज वही भारत अपनी नीतियों पर दृढ़ रहते हुए वैश्विक शक्तियों को भी संवाद और सहयोग के लिए विवश कर रहा है। भारत अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ में की गई यह कटौती इसी बदले हुए वैश्विक दृष्टिकोण का प्रमाण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब भारतीय निर्यातकों पर लगने वाला अतिरिक्त 'पेनल्टी टैरिफ' हट चुका है और केवल रेसिप्रोकल टैक्स स्ट्रक्चर लागू है, जिससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी बन गए हैं।

एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर को मिलेगा सीधा और दीर्घकालिक लाभ

अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में की गई कटौती का व्यापक और प्रत्यक्ष असर उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर पर पड़ने वाला है। भदोही के हस्तनिर्मित कालीन, मुरादाबाद के पीतल व धातु उत्पाद, आगरा का चमड़ा उद्योग, वाराणसी की रेशमी साड़ियां और कन्नौज का पारंपरिक इत्र अब अमेरिकी बाजार में पहले की तुलना में कम लागत और बेहतर लाभांश के साथ पहुंच सकेगा। अब तक ऊंचे टैरिफ के कारण ये उत्पाद कीमत के मामले में चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से पिछड़ जाते थे, लेकिन शुल्क में कमी के बाद उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सकेंगे। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल निर्यात

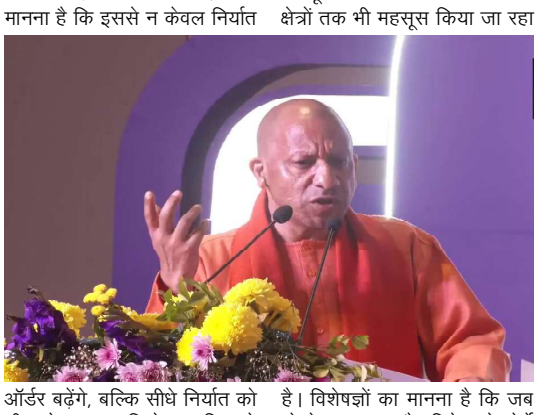

ऑर्डर बढ़ेंगे, बल्कि सीधे निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और कारीगरों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। इसका सकारात्मक असर रोजगार पर भी दिखाई देगा। उत्पादन बढ़ने से बुनकरों, शिल्पकारों, कारीगरों और छोटे उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों को नियमित रोजगार मिलेगा, वहीं नई यूनिट्स की स्थापना से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

डिफेंस कॉरिडोर में तकनीक का होगा प्रवेश

भारत–अमेरिका के बीच टैरिफ में कटौती और व्यापारिक रिश्तों में आई मजबूती का प्रभाव अब रणनीतिक क्षेत्रों तक भी महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब दो देश व्यापार और निवेश के मोर्चे पर एक–दूसरे के प्रति भरोसा जताते हैं, तो उसका स्वाभाविक विस्तार रक्षा और उन्नत तकनीक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी होता है। इसी क्रम में भारत–अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग का सकारात्मक असर उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी दिख सकता है। झांसी, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा जैसे रणनीतिक नोड्स अब केवल असेंबली यूनिट्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त उपक्रमों और उच्चस्तरीय अनुसंधान के माध्यम से उन्नत रक्षा उपकरणों के निर्माण की संभावनाएं आकार ले रही हैं। जानकारों के अनुसार, अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ संभावित सहयोग से ड्रोन सिस्टम, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार एवं राडार सिस्टम तथा अत्याधुनिक कंपोनेंट्स का निर्माण प्रदेश में ही संभव हो सकता है। टैरिफ में कटौती से बने अनुकूल निवेश माहौल और भारत की नीतिगत स्थिरता ने विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ाया है, जिसका लाभ रक्षा क्षेत्र को भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे न केवल आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त होगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलने वाला है। उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स के कारण इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उच्च कौशल आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को भी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय उद्योगों को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

आईटी, जीसीसी और डेटा सेंटर सेक्टर को मिलेगी गति

भारत–अमेरिका के बीच टैरिफ में कटौती और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में आई मजबूती का असर केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार उच्च तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब वैश्विक स्तर पर व्यापार बाधाएं कम होती हैं और नीतिगत स्थिरता का संकेत मिलता है, तो अंतरराष्ट्रीय टेक कंपनियों के लिए निवेश निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश की जीसीसी नीति–2024 को नया बल मिलता नजर आ रहा है। नोएडा और लखनऊ में विकसित हो रहा एआई, आईटी और डेटा सेंटर इकोसिस्टम अब अमेरिकी और अन्य वैश्विक टेक कंपनियों के लिए अधिक आकर्षक बनता जा रहा है। टैरिफ कटौती से आईटी हार्डवेयर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और सेमीकंडक्टर से जुड़ी आयात लागत में संभावित कमी आने से डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स की आर्थिक संभाव्यता और बेहतर होगी। इससे बड़े पैमाने पर कैपिटल–इंटेंसिव निवेश को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि अनुकूल व्यापार माहौल और मजबूत भारत–अमेरिका तकनीकी सहयोग के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ जैसे शहर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के नए हब के रूप में उभर सकते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उच्चस्तरीय कार्य होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर के रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का फोकस डेटा सेंटर, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्थिर बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे पर है। इन कारकों और टैरिफ कटौती से बने सकारात्मक वैश्विक माहौल के चलते डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और आईटी सेवाओं में आने वाले वर्षों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं बन सकती हैं।

फार्मा और ग्रीन एनर्जी में यूपी की रणनीतिक बढ़त

भारत–अमेरिका के बीच टैरिफ में की गई कटौती का सबसे प्रत्यक्ष और संरचनात्मक लाभ फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को मिलने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी बाजार में दवाओं, बल्क ड्रग्स और मेडिकल उपकरणों पर आयात शुल्क कम होने से भारतीय उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धी होगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस बदले हुए परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के लिए अवसर और भी व्यापक हो गए हैं। ललितपुर में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क को लेकर पहले से ही निवेशकों की रुचि रही है, लेकिन टैरिफ में राहत के बाद अब यह परियोजना वैश्विक सप्लाई चेन के लिहाज से और आकर्षक बन गई है। इससे फार्मा कंपनियों को एपीआई (एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इन्ग्रेडिएंट्स) और इंटरमीडिएट्स का उत्पादन प्रदेश में स्थापित करने का आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। जानकारों का मानना है कि इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और यूपी घरेलू के साथ–साथ निर्यात–उन्मुख फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बन सकता है। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी टैरिफ कटौती का सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इमेजिंग उपकरण, डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल उपकरण और अन्य हाई–वैल्यू मेडिकल डिवाइसेज के निर्यात में लागत घटने से उत्तर प्रदेश में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे 'मेक इन इंडिया' के साथ–साथ 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की अवधारणा को भी बल मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, विशेष रूप से बुंदेलखंड के सोलर पार्क और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए भी टैरिफ में राहत एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रोलाइजर और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के आयात–निर्यात में व्यापार बाधाएं कम होने से तकनीक हस्तांतरण और विदेशी निवेश को गति मिल सकती है। अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी से उन्नत तकनीक और पूंजी का प्रवाह बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743